भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 801
26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दीर्घकालिक स्थानिक रोगों का उन्मूलन

801. डॉ. थोल तिरूमावलवन:
डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त परियोजनाओं की लागत और उक्त परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित समय-सीमा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने किसी ऐसे क्षेत्र की पहचान की है जहां तमिलनाडु सहित देश में दीर्घकालिक स्थानिक रोगों के उन्मूलन के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकता हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) तमिलनाडु सहित देश के आकांक्षी जिलों में कार्यान्वित की जा रही उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और ब्यौरा क्या है; और
(च) उक्त परियोजनाओं की और प्रगति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को उनके समग्र संसाधनों के भीतर उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर जिला अस्पतालों तक उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई स्वास्थ्य परियोजनाओं, उनकी लागत, पुरानी स्थानिक

बीमारियों के उन्मूलन के लिए विशिष्ट कार्यक्रम का पूरा विवरण उपलब्ध है और इसे https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744 लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) तमिलनाडु सहित उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां ये रोग स्थानिक हैं, में मलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया और लिम्फैटिक फाइलेरियासिस जैसे छह वेक्टर जनित रोगों (वीबीडी) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) नामक एक व्यापक कार्यक्रम का संचालन करता है। भारत सरकार तमिलनाडु सहित पूरे भारत में खसरा और रूबेला को समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है। इन बीमारियों को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 9 माह और 16-24 माह की आयु के बच्चों को खसरा और रूबेला वैक्सीन की दो खुराकें दी जाती हैं। एक राष्ट्रव्यापी खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान चलाया गया जिसमें 9 माह से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को एमआर वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक दी गई। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, प्रगति और कार्यनिष्पादन का नियमित रूप से समीक्षा बैठकों, क्षेत्र दौरों के साथ-साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी), सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम), स्वास्थ्य निगरानी सूचना प्रणाली (एचएमआईएस), प्रजनन बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पोर्टल, गैर संचारी रोग (एनसीडी) पोर्टल द्वारा वार्षिक कार्यक्रम योजना और समीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है।

(ङ) और (च): आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र से कुल 13 मुख्य संकेतक और 31 उप-संकेतक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के रूप में पहचाने गए हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आकांक्षी जिलों में सुधारात्मक बदलाव लाने के लिए एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य योजना बनाई है। भारत सरकार ने भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस), आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई), निःशुल्क दवा सेवा पहल, मुफ्त डायग्नोस्टिक्स सेवा पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, 15वें वित्त आयोग अनुदान, भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईसीआरपी-I और II पैकेज), राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस), आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन सेवाओं के माध्यम से देश भर में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने की पहल की है।

*****